

## भारत में शिक्षा पर राजनीति का प्रभाव

**आजाद यादव (शोध छात्र)**

शिक्षक प्रशिक्षण विभाग  
शिब्ली नेशनल पी.जी. कालेज  
आजमगढ़



सार –

यह शोध लेख भारतीय शिक्षा प्रणाली पर राजनीति के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। किसी भी देश की शिक्षा उस विशेष राष्ट्र की विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा ही मनुष्य में नैतिकता व मूल्यों को समावेशित कर उन्हें साक्षर एवं सभ्य नागरिक बनाती है। यदि हमारे पास अच्छी तरह से पोषित और संतुलित शिक्षा प्रणाली है तो राष्ट्र के विकास का आधा कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली कई राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक मुद्दों से पीड़ित है। जैसे— भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजावाद और सबसे प्रमुख है— शिक्षा की गुणवत्ता। भारत के सामने जो समस्याएँ हैं उसे हल कर पाना एक कठिन चुनौती है। आज तेजी से बढ़ते तकनीकी युग के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली कंधे से कंधा मिलाकर कार्य नहीं कर पा रही है। इस लेख में हम कुछ स्पष्ट वास्तविकताओं को देखेंगे, जिसके कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली गंभीर संकट में है।

मुख्य शब्द –

शिक्षा, राजनीति, भ्रष्टाचार, जातिवाद और शिक्षा की गुणवत्ता।

उद्देश्य –

इस लेख का उद्देश्य शिक्षा आयोगों एवं सरकार द्वारा शिक्षण स्तर के उत्थान के प्रयास के बावजूद शैक्षिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का आंकलन करना व शिक्षा पर राजनीति के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है।

शिक्षा और राजनीति का एक दूसरे के साथ एक सहजीवी संबंध है। जिसमें यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहता है तो वहाँ एक नकारात्मक वातावरण का सृजन हो जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य की अवधारणा की संकल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा और राजनीति की कल्पना दो अलग-अलग रूपों में की जा सकती है। पहला, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली राजनीति का शिक्षा पर प्रभाव

का एक निश्चित स्तर तो दूसरी ओर औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से शिक्षा का राजनीति पर प्रभाव।

भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ सबसे ज्यादा राजनीतिक दल भी है। भारत में विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय, राज्य के एवं स्थानीय स्तर पर अलग-अलग राजनीतिक मद्दे होते हैं। जिनमें भ्रष्टाचार जाति, धर्म, बेरोजगारी आदि महत्वपूर्ण मद्दे हैं। जिनको सुलझा पाना इन सभी दलों के लिये एक टेढ़ी खीर है। शिक्षा की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास और अस्तित्व के लिए शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। भारत पहला देश है, जहाँ शिक्षा राजनीति का शिकार है। कभी प्रबंध तंत्र के स्तर पर, कभी शिक्षक के तो कभी छात्रों के स्तर पर या फिर इन सभी स्तरों पर। यहाँ शैक्षणिक संस्थाएँ भी जातिगत व साम्प्रदायिक आधार पर चलती हैं। अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक आधार पर भी शिक्षण संस्थाओं का विभाजन सरकार की नीति का ही परिणाम है। आज धर्म, शिक्षण व राजनीतिक संस्थाओं दोनों के लिए एक भय का विषय बन गया है। अगर शिक्षण

संस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता को नजर अंदाज कर दिया जायेगा तो ये नौजवानों व लोकतंत्र दोनों के लिए एक खतरा हो जायेगा। धर्म और शिक्षा को समन्वित कर देने से साम्प्रदायिकता का खतरा सदैव मँडराता रहता

है। धर्म अंधविश्वास को जन्म देता है तो दूसरी ओर विज्ञान और प्रौद्योगिक हमें तथ्यों के आधार पर विकासोन्मुख करने का प्रयास करते हैं। तब बात यह उठती है कि जब संस्थायें निर्मित ही विभाजन के आधार पर हों तो शिक्षा का भविष्य क्या होगा ?

शिक्षा सीधे तौर पर समाज से जुड़ी होनी चाहिये परंतु हमारी शिक्षा में समाज के आवश्यक एवं वैकल्पिक प्रश्नों के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है। शिक्षा आर्थिक युग का भी पूरा-पूरा फायदा उठा रही है। वह कई स्तरों पर बँट गयी है—म्यूनिसिपल, कान्वेन्ट, मांटेसरी, कैंश या सेंट्रल बोर्ड स्तर पर। ज्यादातर स्तरों पर अभी तक हम अतीत में निर्धारित मानकों के आधार पर ही शिक्षा दे रहे हैं, जो अधूरी शिक्षा है। यह हमें अंतर्दृष्टि नहीं देती क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परीक्षा में उत्तीर्ण होना। जिसमें परीक्षक का मुड या परीक्षक का बौद्धिक वर्गवाद भी शामिल है। हमारी शिक्षा भविष्य की बेदी पर कभी वर्तमान की बलि चढ़ाती है तो कभी वर्तमान की बेदी पर भविष्य की। हमारी शिक्षा में पाया-खोया का सिद्धांत आवश्यक है इसी आधार पर व्यक्ति की श्रेष्ठता व निकृष्टता निश्चित की जाती है। कितना हास्यास्पद है कि वर्ष भर छात्र जो करता है वह निर्णायक नहीं होता, निर्णायक होता है तीन घंटे में हल किये गये कुछ चंद सवाल।

शिक्षा का वास्तविक कार्य मनुष्य के विवेक को जागृत कर उसे न्यायपूर्ण, नैतिक, सच्चा, ईमानदार तथा कर्मठ नागरिक बनाना है। जिनके आधार पर एक बुद्धिजीवी नागरिक के रूप में

शिक्षा ही मनुष्य में नैतिकता व मूल्यों को समावेशित कर उन्हें साक्षर एवं सभ्य नागरिक बनाती है। यदि हमारे पास अच्छी तरह से पोषित और संतुलित शिक्षा प्रणाली है तो राष्ट्र के विकास का आधा कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में देखे तो भारतीय शिक्षा प्रणाली कई राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक मुद्दों से पीड़ित है। जैसे— भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजावाद और सबसे प्रमुख है— शिक्षा की गुणवत्ता।

देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी समस्याओं के विषय में स्पष्ट रूप से चिन्तन करके अपना निजी निर्णय ले सके और उन्हें सुलझा सके। सत्य, असत्य तथा वास्तविकता एवं प्रचार में अन्तर समझते हुए अन्ध विश्वासों तथा निरर्थक परम्पराओं का उचित विश्लेषण करके अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा अपना निजी निर्णय ले सकें। प्लेटो व अरस्तू के काल से ही चिन्तक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जब तक राजनीति के साथ नैतिक तत्व नहीं जुड़ेगा तब तक उसके अस्वच्छ रूपों का शमन नहीं किया जा सकता। शिक्षा ही समाज तथा राष्ट्र के चरित्र का निर्माण कर सकती है। शिक्षा प्रणाली का आधार होते हैं राष्ट्र के उद्देश्य जिनकी

पूर्ति के लिये राज्य की शासन व्यवस्था की ईमानदारी, क्रियाशीलता व सक्षमता उत्तरदायी है। ये सभी तथ्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से राष्ट्र की जीवन प्रक्रिया के रथ को आगे बढ़ाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा समाज की पुनर्रचना के प्रबल अभिकरण है, किन्तु तभी जब शिक्षा राजनीति निरपेक्ष हो और राजनीति शिक्षित व्यक्ति सापेक्ष हो बहुमत के आधार पर भेड़चाल की राजनीति दिशाहीन व विवेकहीन राजनीति होती है। शिक्षा और राजनीति मानव का अन्तर्वाह्य कवच है, जिनके द्वारा मानवता की बर्बरता स्वार्थ लोलुपता और अराजकता से रक्षा होती है।

किन्तु क्या वर्तमान में राजनीति और शिक्षा से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है जिनके लिये भारतीय संविधान में हमने शपथ ली थी? क्या आज देश के कोने-कोने में विभिन्न मुद्दों को लेकर हड़ताल, हत्याएँ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, औषधियों में मिलावट, कराडो रूपये खर्च कर मंदिरापन कराकर वोट प्राप्त करने की राजनीति हमें सकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि शिक्षा का व्यक्ति और समाज सापेक्ष न होने का ही यह दुष्परिणाम है कि आज का युवक बेरोजगारी का शिकार हो गया है? शिक्षा न हमें ज्ञान दे पा रही है न शान्ति और न समाज के साथ एकात्मकता की हमें अनुभूति ही करा पा रही है। यदि देश को शत-प्रतिशत शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात स्वतंत्रता मिलती तो प्रजातंत्र अधिक सफल होता। दुर्भाग्य से 71 वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं

कर सका है बढ़ती हुई साक्षर अज्ञानता का परिणाम यह हुआ कि राजनीति लोगो का पेशा बन गया है और शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है।

भारतीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसकी निम्न गुणवत्ता। गुणवत्ता एवं शिक्षा के मानको में विभिन्न राज्यों में भिन्नताये हष्टिगत होती है। महिलाओं के साक्षरता के आधार पर यदि हम देखें तो बिहार में 34 प्रतिशत हैं। और केरल में 88 प्रतिशत का आँकड़ा है और पुरुषों की बात करें तो बिहार में 60 प्रतिशत तो केरल में 94 प्रतिशत है। राजस्थान में सबसे बड़ा लिंग भेद हैं, अगर महिला साक्षरता 44 प्रतिशत हैं तो पुरुष की 77 प्रतिशत है। सरकारें आती जाती हैं। लेकिन अंत में आशाओं का एक रहस्य छोड़ जाती है जहाँ एक तरफ जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत तक शिक्षा पर खर्च करने का संकल्प लिया गया। लेकिन वास्तविकता में यह आकड़ा 4 प्रतिशत के आसपास ही मँडराता रहा। इतने सारे संशोधन किये गये नीतियाँ बनी, आयोगो की स्थापना की जाती रही, लेकिन ये सब वास्तविकता के घरातल पर खड़ी नहीं हो पायी और शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार इसे और घातक बनाने का कार्य करता रहा। जहाँ एक आदर्श व्यवस्था के रूप में शिक्षा को उभरना चाहिये था वहाँ भ्रष्ट नेताओ व उद्योगपतियों को लाभान्वित करने की योजनाएँ ज्यादा कारगर रूप से लागू की जाती रही। भ्रष्टाचार के रूप अलग-अलग है जैसे रिश्वत, भाई-भतिजावाद, जातिवाद, गबन और नाजायज संरक्षण। शिक्षा में बढ़ते निवेश के बावजूद यहाँ की 35 प्रतिशत आबादी निरक्षर है। केवल 15 प्रतिशत भारतीय छात्र हाईस्कूल तक पहुँचते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत स्नातक स्तर तक। राष्ट्रभर में 25 प्रतिशत पद रिक्त हैं और 57 प्रतिशत शिक्षकों में गुणवत्ता की कमी हैं। शिक्षक ने यदि तीस साल पहले शिक्षा पाई हैं तो वह तीसों साल से वही दुहराते आ रहे हैं। जब कि परिस्थितियाँ निरन्तर बदलती रहती है। ज्ञान राशि नित्य बढ़ रही है। हर क्षण हमारे प्रति संवेदन पुराने पड़ने जा रहे हैं। स्थिति यह है कि किसी भी विषय पर अब किताब नहीं लिखी जा सकती क्योंकि जितने दिन में किताब पूरी होगी नए आवष्कार नए तथ्य पुस्तक को असंगत कर देते हैं। फिर भी शिक्षक वही पुराना तथ्य पढ़ाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसकर उन्हे राज्य से पुरस्कार भी प्राप्त हो जाता है।

एक ही समूह के मध्य आय की असमानता भी शिक्षण गुणवत्ता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो अमीर अमीर होता जायेगा और गरीब गरीब। निजी एवं सरकारी स्कूल के अंतर को समाप्त करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में निरन्तर "ह्रास का एक और कारण अपर्याप्त शिक्षण सुविधाये भी है। यदि संस्थाओ की बात की जाए तो भारत मे 20 केन्द्रीय 215 राज्य विश्वविद्यालय 100 डीमड विश्वविद्यालय, 1800 अन्य संस्थान, 16000 कालेज (सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित ) एवं महिला महाविद्यालय है। किन्तु संख्या से गुणवत्ता ज्यादा



मायने रखती है। विश्व बैंक के आँकड़ों से यह पाया गया कि भारत में किशोरों की संख्या 40 प्रतिशत से भी कम हैं, जो माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा ले सकें। द इकोनोमिस्ट की रिपोर्ट है कि 10 साल के ग्रामीण बच्चों में से आधे भी मूल स्तर तक नहीं पढ़ पाये और वे पढ़ाई में 60 प्रतिशत से अधिक लाने में असमर्थ थे। तो क्या यही नींव है जिस वर आज 2020 में भारत एक महाशक्ति के रूप में खड़े होने के स्वप्न देख रहा है। क्या हमारी शक्ति इतनी बढ़ पाती है कि हम चीन, ब्रिटेन, यू एस ए जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर सकें।

संक्षेप में आज शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार के कारण आयोग्य शिक्षकों की भरमार हो गयी है। सभी सरकारें जाति व सम्प्रदाय के आधार पर भी शिक्षकों का चुनाव करती रही आज शिक्षक छात्रों में सरकार के प्रचार-प्रसार का एक माध्यम बन गये हैं। शैक्षणिक संस्थान एक निश्चित ब्रॉण्ड की राजनीति के विज्ञापनकर्ता बन गए हैं, बैठकों और अभियानों के माध्यम से छात्रों को प्रभावित करते रहते हैं। परिसर के भीतर जूझ रहे छात्रों के कुछ समूह अराजकता फैलाने के कार्य में संलिप्त रहते हैं। जिससे सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और एक स्वस्थ शांतिपूर्ण नैतिक और अनुशासन का माहौल सृजित होना असंभव हो जाता है। भारत के विश्वविद्यालयों अथवा कालेजों में छात्र अभियान उनके राष्ट्रीय सहयोगियों द्वारा वित्तपोषित होते हैं और वे धन, समय एवं अन्य संसाधनों की पूर्णतया बर्बादी करते हैं। छात्रों के ये समूह विचारधारा में शून्य हैं। ये ज्यादातर राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं इनके दिग्भ्रमित होने की संभावना सदैव ही बनी रहती है। आज सी.ए.ए. को लेकर जे एन यू व जामियाँ अन्य संस्थानों में हो रहे आंदोलन उसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

बाहरी राजनीति दल भी अपने छात्र सहयोगियों को जबरन वसूली करने के लिए मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। बदले में पार्टियाँ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के चुनाव के दौरान पारंपरिक प्रचार के लिए या और भी संदिग्ध उद्देश्यों के लिए इन छात्रों के पंखों का उपयोग करती हैं जैसे मतदाताओं को विशिष्ट उम्मीदवारों को चुनने से डराने के लिए पोलिंग बूथ पर ले जाना। दूसरे शब्दों में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए कालेज परिसर उनके वास्तविक राजनीतिक जीवन का एक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ये दल शायद ही कभी छात्रों का ध्यान आवास की कमी या कालेज कैण्टीन के भोजन में गुणवत्ता की कमी की ओर आकर्षित करते हैं बल्कि वे अकसर जाति व धर्म के आधार पर छात्रों में विभेद पैदा करते हैं और इन्हीं आधारों पर उन्हें वोट देने का भी आग्रह करते हैं।

बेरोजगारी इतनी ज्वलन्त समस्या है जिसके कारण छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा है और चोरी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनायें सामने आती हैं जो समाज के वातावरण को दूषित करती हैं। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है अर्थात् जब छात्रों के मन में ये बात घर कर जाती है कि पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका ध्यान पढ़ाई

से हटकर अन्य चीजों में ज्यादा लगता है जो कभी-कभी उन्हें गलत रास्तों पर ले जाती है जहा से लौट पाना उनके लिये मुश्किल और कभी-कभी तो नामुमकिन हो जाता है।

अब यदि हम शिक्षा पर राजनीति के सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि युवा लॉग मतदाता आबादी का एक बड़ा हिस्सा होते हैं इसलिये ये आवश्यक है कि उन्हें राजनीतिक मुद्दों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो क्योंकि राजनीतिक फैसले सीधे तौर पर किसी भी देश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं आज हम अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं को विवेकपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए देखते हैं ऐसे में छात्रों को विपक्ष के वर्कपूर्ण निर्णयों को समझने और स्वयं सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिये। राजनीति युवाओं को उनके अधिकारों एवं उनके अधिकारों के समुचित उपयोग के लिये उन्हें जागरूक करती है राजनीति से दूरी वर्तमान घटनाओं व देश में हो रही वारदातों से हमें उदासीन बना देती है। जिस प्रकार छात्रों को इंजीनियर डाक्टर बनने के लिए तैयार किया जाता है उसी प्रकार उन्हें एक अच्छा राजनीतिक भी बनाया जा सकता है। जो स्वयं को देश सेवा में समर्पित कर सकें युवा मतदाता वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हैं अगर उनमें राजनीतिक जागरूकता का संचार नहीं हुआ तो देश का समुचित विकास असंभव हो जायेगा। कॉलेज की बहस और मुक्त भाषण से कालेज में एक जीवन्तता पैदा होती है। विश्वविद्यालय भविष्य के रानेताओं के लिए एक नर्सरी है और मुख्यधारा की राजनीति पर पूर्ण प्रतिवन्ध लगाना जो उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार में छात्रसंघ चुनावों को समाप्त कर लगा दिया था सर्वथा अनुचित है क्योंकि ऐसा कार्य छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनने के मूलभूत अवसर से वंचित करता है। किसी भी छात्र को राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने, एक शांतिपूर्ण माहौल में रहकर अनुशासित व्यवहार के साथ अपनी बात रखने व बहस करने के अवसर प्रदान करने से इन्कार करना अलोकतान्त्रिक है जो एक स्वस्थ व नैतिक वातावरण के सृजन में बाधक होता है। राजनीति एक सामाजिक विज्ञान है और संगठित आंदोलनों के माध्यम से व्यवस्था को परिष्कृत व परिमाजित किया जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश की जनता में राजनीतिक अज्ञानता अत्याचार के बढ़ने, निरंकुशता तथा लोकतंत्र के पतन का मार्ग प्रशस्त करती है।

#### **निष्कर्ष —**

भारत सरकार को शिक्षा में हो रहे भ्रष्टाचारों को हल करने के उपाय खोजकर उसका सम्यक समाधान करना चाहिए। ताकि कोई भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय तथा घुसखोरी के आधार पर शिक्षा को पतन की ओर न ले जा सके। शिक्षा के आगत शिक्षक हैं जो छात्रों को उच्च कौशल वाले नागरिक हैं उनमें नैतिकता, न्याय, सदाचार की भावना जागृत कर बनाते आने वाली पीढ़ी के लिए एक मॉडल तैयार करते हैं। ये शिक्षा का सकारात्मक पक्ष है। जिसके लिए

शिक्षक गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। डा० अब्दुल कलाम आजाद के इन शब्दों को अगर ध्यान दें कि 'जब सीखना है तो उद्देश्यपूर्ण रचनात्मकता आवश्यक है। जब रचनात्मकता होती है तो सोच निकलती है जब सोच निकलती है तो ज्ञान पूरी तरह से जगाया जाता है, जब ज्ञान जगाया जाता है तो अर्थव्यवस्था फूलती-फलती हैं। तो हम ये पाते हैं कि देश और उसकी अर्थव्यवस्था के शत प्रतिशत निर्माण में शिक्षित नागरिक व शिक्षकों की अहम भूमिका है। अगर सकारात्मक कदम लिये गये तो भारत भी समृद्धि ज्ञान का दावा करने में सक्षम होगा। देश की संस्कृति उन्नति होगी और शिक्षा भी अन्य क्षेत्रों की तरह अपना वर्चस्व दिखाने में सक्षम होगी।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची:-**

- (1) ब्लैकवेल, फ्रिट्ज़ (2004), भारत: एक वैश्विक अध्ययन पुस्तिका ,संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका: ABC- CLIO, Inc., आईएसबीएन 1.57607.348.31
- (2) भारत 2001 1: एक संदर्भ वार्षिक (53 वाँ संस्करण) , नई दिल्ली: अतिरिक्त महानिदेशक (ADG), प्रकाशन विभाग, सूचना मंत्रालय और प्रसारण, भारत सरकार, आईएसबीएन 978-81-230-1557-6।
- (3) प्रभु, जोसेफ (2006), शैक्षिक संस्थान और दर्शन, पारंपरिक और पारंपरिक और आधुनिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ इंडिया (खंड 1 2) स्टेनली वोल्पर द्वारा संपादित थॉमसन गैल: आईएसबीएन 0-684-31351-0।
- (4) रमन, एसए (2006)। महिला शिक्षा , भारत का विश्वकोश (खंड 4),
- (5) रमन, एसए (2006)। महिला शिक्षा , भारत का विश्वकाश (खंड 4), स्टेनली वोल् 235-239, थॉमसन गैल द्वारा संपादित: आईएसबीएन 0-684-31353-7।
- (6) सेट्टी, ईडी औरॉस, ईएल (1987), ए केस स्टडी इन एप्लाइड एजुकेशन इन ग्रामीण भारत, सामुदायिक विकास जर्नल, 22 (2): 120-129, ऑक्सफोर्ड विश्व – विविद्यालय का मुद्रणालय।
- (7) श्रीपति, वी। और थिरुवेंगडम, एके (2004), संवैधानिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का संशोधन, संवैधानिक कानून के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2 (1): 148-158, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दवाएँ।
- (8) मेहता, अरुण सी। भारत में शैक्षिक सूचना प्रणाली और इसकी सीमाएँ: सुधार के सुझाव: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान और शासन प्रबंध। नई दिल्ली।